संरक्षकः मां वैष्णो देवी
राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र

PRN: MCN/111/2024-2026
RNI. No. MAHHIN/2008/28092

सुबह से शाम

S.S. Media Group

तक की खबरें

मूल्य - 2₹

विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें

अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो साप्ताहिक **'सुबह से शाम तक की खबरें'** आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन कीबधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनीनोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।

ईमेलः Email Id - ssnews2008@gmail.com
या वाट्सऐप नं. 8898330400

* वर्षः 19 * अंकः 21 * मुंबई, रविवार, 1 नवंबर से 7 नवंबर 2026 * संपादकः- एस.के.तिवारी * पेजः 4 Email Id - ssnews2008@gmail.com www.subahsesham.com

सिंहस्थ कुंभ 2027 का शंखनाद: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नासिक के रामतीर्थ पर धर्मध्वजारोहण

साधु-संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच फहराई भगवा धर्मध्वजा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजित पवार सहित कई मंत्री रहे उपस्थित





संवाददाता

नासिक। गोदावरी के पावन तट पर स्थित रामतीर्थ में शनिवार को नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभपर्व के शुभारंभ का भव्य धार्मिक समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों भगवा धर्मध्वजा फहराई गई। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और साधु-संतों की उपस्थिति में संपन्न इस समारोह ने पूरे नासिक शहर को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया। बारह वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभमेले की तैयारियों और धार्मिक परंपराओं के लिहाज से इसे ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले यज्ञकुंड में आहुति अर्पित की। इसके बाद जीवनदायिनी गोदावरी का विधिवत पूजन कर धर्मध्वज को नमन किया। पुरोहितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनके हाथों धर्मध्वजारोहण संपन्न हुआ। जैसे ही भगवा धर्मध्वजा आकाश में लहराई, शंखनाद और मंगलवाद्यों की ध्वनि से रामतीर्थ का परिसर गूंज उठा। इसके बाद मंत्रपुष्पांजलि अर्पित की गई। यज्ञाहुति, गोदावरी पूजन, ध्वज पूजन और धर्मध्वजारोहण के धार्मिक अनुष्ठानों ने सिंहस्थ पर्व के आगमन को पारंपरिक धार्मिक आधार प्रदान किया।

राष्ट्रपति के साथ उपमुख्यमंत्री और कई मंत्री रहे मौजूद

इस ऐतिहासिक समारोह में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, केंद्रीय आयुष एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, पालकमंत्री गिरीश महाजन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, विपणन एवं राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल और मत्स्य व्यवसाय एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे उपस्थित रहे। महापौर हिमगौरी आडके-आहेर, सांसद राजाभाऊ वाजे, सांसद भास्कर भगरे और सांसद डॉ. शोभा बच्छाव सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी समारोह में भाग लिया।

धर्मध्वजारोहण के पवित्र विधानों से सिंहस्थ को मिला धार्मिक आधार

समारोह में भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार प्रत्येक धार्मिक विधि पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न की गई। यज्ञकुंड में आहुति अर्पित करने के बाद गोदावरी पूजन और धर्मध्वज की पूजा की गई। पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच धर्मध्वजारोहण हुआ। शंखनाद, मंगलवाद्य और मंत्रपुष्पांजलि के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। गोदावरी के तट पर फहराई गई धर्मध्वजा को देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिंहस्थ **(शेष पेज 2 पर)**

प्रतिबंधित पदार्थों पर कार्रवाई में अनियमितता पर FDA के चार अधिकारी निलंबित

दिगंबर भोगावडे, यदुराज दहातोंडे, अशोक इलागेर और सी. आर. स्वामी पर गिरी गाज, 21 अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू



संवाददाता

मुंबई। प्रतिबंधित तंबाकूजन्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने अन्न व औषधि प्रशासन (FDA) के चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 21 अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। यह कार्रवाई ठाणे की मेसर्स हाईस्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी और मावल तालुका की मेसर्स सोएक्स इंडिया प्रा. लि. से जुड़े मामलों में की गई है। इसकी जानकारी मंत्री नरहरि झिरवाल ने दी। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के माध्यम से कराई गई जांच के बाद अन्न सह आयुक्त दिगंबर भोगावडे, अन्न सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर और सी. आर. स्वामी को 30 अक्टूबर 2026 के आदेश के तहत निलंबित किया गया है। महाराष्ट्र नागरी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 के नियम 8 के तहत आगे की विभागीय जांच शुरू की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार, हाईस्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी के मामले में उत्पाद पर 'नॉट फॉर एडिबल यूज/ओन्ली फॉर यूज इन हुक्का फॉर स्मोकिंग पर्पज' लिखा होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए दबाव डालने और कार्रवाई से इनकार करने वाले सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का भी उल्लेख है। वहीं, मावल तालुका के टाकवे स्थित सोएक्स इंडिया प्रा. लि. कंपनी पर 2 जनवरी 2026 को की गई कार्रवाई में 31 करोड़ 67 लाख 21 हजार 987 रुपये मूल्य का 5 लाख 48 हजार 488 किलो प्रतिबंधित तंबाकूजन्य पदार्थों का भंडार जब्त कर कंपनी का प्रतिष्ठान सील किया गया था।

दोनों मामलों में संबंधित अधिकारियों की भूमिका, कार्रवाई की कानूनी वैधता, अधिकार क्षेत्र और प्रशासनिक प्रक्रिया के पालन की जांच की जाएगी। मंत्री झिरवाल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में कानून का पालन तथा प्रशासनिक जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी।

जेल से रिहा होते ही ईडी की कस्टडी में गए आजम खान, बोले- मुसलमान होना गुनाह है

दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से निकले सपा नेता, बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई की प्रक्रिया भी पूरी



संवाददाता

रामपुर, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान रामपुर जिला जेल से रिहा होते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में चले गए। दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी जेल से रिहाई हुई। जेल से बाहर निकलते समय आजम खान ने कहा, "कहने को बचा ही क्या है।

इस देश में मुसलमान होना गुनाह है। यह मुसलमान होने की सजा है। एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बनाई, यह गुनाह है। मुसलमान ने बच्चों और समाज के लिए स्कूल बनाए, यह भी गुनाह है। आजम खान और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों के रिहाई परवाने रामपुर जिला कारागार पहुंच गए थे। इसकी जानकारी मिलते ही जेल के बाहर समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी। हालांकि, आजम खान की रिहाई के बाद ईडी की कस्टडी में जाने से घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया।

जमानत से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी

दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिन मामलों में दोनों जेल में बंद थे, उनमें जमानती बांड और श्योरिटी दाखिल की गई। संबंधित अदालतों में इनके सत्यापन के बाद रिहाई के आदेश जारी किए गए। आजम खान के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान के मुताबिक, दोनों नेताओं से जुड़े सभी मामलों में जमानती बांड और श्योरिटी का सत्यापन पूरा हो चुका था। इसके बाद अदालतों ने रिहाई के आदेश जारी किए।

जेल के बाहर जुटे समर्थक

रिहाई की खबर मिलते ही सपा कार्यकर्ता और समर्थक जेल के बाहर पहुंचने लगे। कई लोग फूल-मालाएं लेकर आए थे और अपने नेता के समर्थन में नारे लगा रहे थे। जेल के बाहर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों के लोग भी मौजूद दिखाई दिए। जेल के बाहर मौजूद समर्थकों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। उनका कहना था कि आज का दिन उनके लिए बेहद खास है और इस खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। किसी ने इसे दिवाली जैसा दिन बताया तो किसी ने कहा कि आज ईद जैसी खुशी मिली है. समर्थकों के मुताबिक, लंबे इंतजार के बाद आई यह खबर उनके लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है।

राज्यपाल ने सरदार वल्लभभाई पटेल और इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि



संवाददाता

मुंबई। देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने लोकभवन में सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राज्यपाल ने उनके चित्र पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने लोकभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना योगदान देने का संकल्प भी लिया।

महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने पर सख्ती पांच साल में 15.46 करोड़ रुपये का जुर्माना

1,045 मामले दर्ज, 976 का निपटारा, 9.39 करोड़ रुपये की वसूली



संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए मत्स्य व्यवसाय विभाग की ओर से नियमित गश्त, विशेष दस्तों के माध्यम से निगरानी और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। नवंबर 2021 से अक्टूबर 2026 तक अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ कुल 1,045 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 976 का निपटारा किया जा चुका है। इन मामलों में कुल 15.46 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि 9.39 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। यह जानकारी मत्स्य व्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे ने दी। महाराष्ट्र के समुद्री मत्स्य संसाधनों का संरक्षण, अवैध मछली पकड़ने पर रोक और समुद्री मत्स्य पालन से जुड़े कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम, 1981 और संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवैध मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर नियंत्रण रखने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों, सुरक्षा रक्षकों और पुलिसकर्मियों के सहयोग से गश्त की जाती है। इसके अलावा, अवैध एलईडी और पर्ससीन मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए विशेष दस्ते भी गठित किए गए हैं।

विभिन्न प्रकार की अवैध मछली पकड़ने पर कार्रवाई

विभाग की ओर से एलईडी और एलईडी पर्ससीन, पर्ससीन और मिनी पर्ससीन, ट्रॉलिंग तथा दूसरे राज्यों से आने वाली मछली पकड़ने वाली नौकाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पर्ससीन और मिनी पर्ससीन मछली पकड़ने के मामलों में 364 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। वहीं, एलईडी और एलईडी पर्ससीन मछली पकड़ने के मामलों में 7.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दूसरे राज्यों की मछली पकड़ने वाली नौकाओं के खिलाफ 103 रिपोर्ट दर्ज कर 3.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नए मछली पकड़ने के मौसम में 31 नौकाओं पर कार्रवाई

नए मछली पकड़ने के मौसम में अवैध गतिविधियों में शामिल 31 नौकाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक, रत्नागिरी में 12, मुंबई शहर में 9, सिंधुदुर्ग में 7, रायगढ़ में 2 और ठाणे-पालघर जिले में 1 मामला दर्ज किया गया है।

ड्रोन से भी रखी जा रही है निगरानी

समुद्र में अवैध मछली पकड़ने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्रोन से प्राप्त जानकारी के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन के माध्यम से दर्ज **(शेष पेज 2 पर)**

महाराष्ट्र में चारा संकट से निपटने के लिए सरकार का बड़ा एक्शन प्लान

जिला वार्षिक योजना के कम से कम 5% फंड से होगा चारा उत्पादन, चारा बैंक, हाइड्रोपोनिक्स और डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू होगी



संवाददाता

मुंबई। अल-नीनो के प्रभाव से इस वर्ष बारिश में कमी और सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने का व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत जिला वार्षिक योजनाओं के कम से कम 5 प्रतिशत फंड का उपयोग चारा उत्पादन, उपलब्ध चारे के संरक्षण और वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए किया जाएगा। पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने बताया कि चारा बैंक स्थापित करने, हाइड्रोपोनिक्स और अजोला पद्धति से चारा उत्पादन तथा जरूरत के अनुसार जिलों के बीच चारे की आपूर्ति जैसे उपाय किए जाएंगे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने 27 अक्टूबर की बैठक में अध्ययन समूह की सिफारिशों को मंजूरी दी। इसके बाद 30 अक्टूबर 2026 को शासनादेश जारी किया गया।

चारा उत्पादन बढ़ाने पर जोर

रबी सीजन में चारे के बीजों की कमी रोकने के लिए महाबीज और अन्य बीज उत्पादकों के माध्यम से बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। कम पानी में उगने वाली और एक से अधिक बार कटाई वाली फसलों को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि विश्वविद्यालयों, बीज केंद्रों, कृषि महामंडल और पशुसंवर्धन विभाग की जमीन पर मक्का, ज्वार, बाजरा सहित विभिन्न चारा फसलें उगाई जाएंगी। गोचर, बंजर और वन क्षेत्रों में उपलब्ध घास का भी संरक्षण कर पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

चारा बैंक और कीमतें तय

जिलावार चारा बैंक स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों, कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जाएगी। चारा काटने और गठ्ठर बनाने वाली मशीनें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने परिवहन खर्च छोड़कर सूखे चारे की अधिकतम कीमत 12 रुपये प्रति किलो और मुरघास की 8 रुपये प्रति किलो निर्धारित की है।

हाइड्रोपोनिक्स और अजोला को बढ़ावा

पशुपालकों के लिए चारा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। इसमें चारे की कटाई, भंडारण, मुरघास बनाने और धान के पुआल के बेहतर उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पारंपरिक चारे पर निर्भरता कम करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स, अजोला और कांटारहित नागफनी की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। पशु चिकित्सालयों में भी प्रायोगिक तौर पर इन विधियों से चारा उत्पादन की योजना है।

चारे के अन्य उपयोग पर रोक

चारा संकट के दौरान **(शेष पेज 2 पर)**

मुंबई में कचरा फेंकने वालों पर AI कैमरे की नजर लाउडस्पीकर से मिलेगा सफाई का संदेश

बीएमसी ने माहिम के गजानन वाटिका में शुरू किया प्रायोगिक उपक्रम, सफलता मिलने पर शहर के अन्य इलाकों में भी लगाए जाएंगे कैमरे

संवाददाता

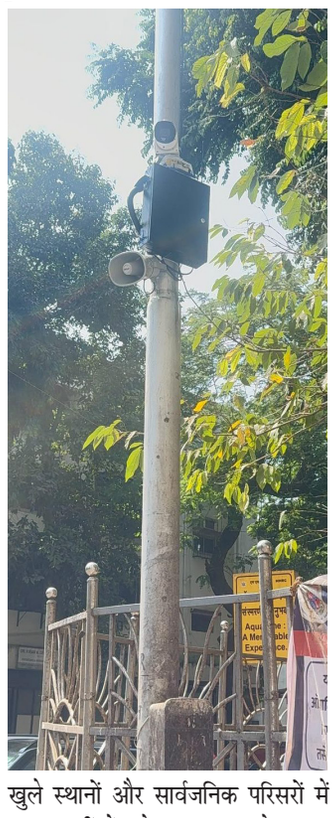
मुंबई। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने की समस्या से निपटने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने तकनीक का सहारा लिया है। कचरा जमा होने की आशंका वाले स्थानों (Garbage Vulnerable Points–GVPs) पर गंदगी रोकने के लिए अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पहल के तहत बीएमसी के जी-उत्तर विभाग ने माहिम स्थित गजानन वाटिका परिसर में एक AI कैमरा लगाया है।

कचरा फेंकते ही लाउडस्पीकर से मिलेगा संदेश

इस कैमरे के साथ लाउडस्पीकर भी लगाए गए हैं। यहां कचरा फेंकने के लिए आने वाले व्यक्ति की गतिविधि कैमरे में दर्ज होती है। इसके बाद लाउडस्पीकर के माध्यम से तत्काल परिसर को स्वच्छ रखने और खुले में कचरा नहीं फेंकने की अपील की जाती है। बीएमसी का उद्देश्य इस व्यवस्था के जरिए लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने से रोकना और उनकी आदतों में सकारात्मक बदलाव लाना है। यह प्रायोगिक उपक्रम बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के निर्देश पर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन तथा उप आयुक्त (ठोस कचरा प्रबंधन) किरण दिघावकर के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छता संबंधी प्रयासों का हिस्सा है। उप आयुक्त (परिमंडल-2) प्रशांत सपकाले और जी-उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त योगेश देसाई की पहल पर इसे शुरू किया गया है।

सफलता के आधार पर अन्य इलाकों में होगा विस्तार

बीएमसी इस प्रयोग की प्रभावशीलता का आकलन करेगी। यदि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, तो भविष्य में मुंबई के अन्य स्थानों पर भी ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। महानगरपालिका ने नागरिकों से सड़कों, खुले स्थानों और सार्वजनिक परिसरों में कचरा नहीं फेंकने तथा शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की है।



संपादकीय



दवा फैक्ट्रियों पर संकट!



अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर अब केवल पेट्रोलियम पदार्थों तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी आंच भारत के कृषि क्षेत्र, उद्योग और दवा कारोबार तक पहुंचने लगी है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के दवा उद्योग पर बढ़ता दबाव इस बात का संकेत है कि दुनिया के किसी एक हिस्से में होने वाला युद्ध हजारों किलोमीटर दूर स्थित देशों की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए अधिक चिंताजनक है, क्योंकि देश दुनिया के प्रमुख दवा उत्पादकों में शामिल है और बड़ी संख्या में दवा कंपनियां कच्चे माल तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर हैं। हिमाचल प्रदेश का बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र और हरियाणा के दवा उत्पादन केंद्र देश के फार्मास्यूटिकल उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों के साथ-साथ हजारों लघु एवं मध्यम उद्यम भी सक्रिय हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण समुद्री परिवहन मार्गों पर दबाव, माल ढुलाई की बढ़ती लागत और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता ने इन इकाइयों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय औषधीय अवयवों (एपीआई), सॉल्वैंट्स और पेट्रोकेमिकल आधारित सामग्री की कीमतों में वृद्धि से उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है। दवा उद्योग की एक बड़ी चुनौती पैकेजिंग सामग्री की बढ़ती कीमतें भी हैं। बोतलें, प्लास्टिक कंटेनर, शीशियां और अन्य पैकेजिंग उत्पाद पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से तैयार होते हैं। जब कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, तो इसका सीधा असर दवा कंपनियों के खर्च पर पड़ता है।

पहले से ही कम लाभ के मार्जिन पर काम कर रही छोटी कंपनियों के लिए लागत में अचानक वृद्धि को सहन करना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें उत्पादन घटाने, नए ऑर्डर रोकने या नुकसान उठाकर कारोबार जारी रखने जैसे कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है। इस संकट का एक मानवीय पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दवा उद्योग में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करते हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतें, रसोई गैस की उपलब्धता और रोजमर्रा के खर्चों में वृद्धि उनके जीवन को प्रभावित करती है। आर्थिक असुरक्षा बढ़ने पर श्रमिकों का पलायन या काम में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। इसका असर उत्पादन क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ना स्वाभाविक है। किसी भी उद्योग की मजबूती केवल मशीनों, निवेश और कच्चे माल से तय नहीं होती, बल्कि उसमें काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह संकट एक पुरानी कमजोरी की ओर भी ध्यान खींचता है। दवा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद देश कई आवश्यक कच्चे माल और एपीआई के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। वैश्विक तनाव, व्यापारिक प्रतिबंध या समुद्री मार्गों में बाधा आने पर इस निर्भरता की कीमत घरेलू उद्योग को चुकानी पड़ती है। इसलिए केवल अस्थायी शुल्क छूट या राहत पैकेज से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। देश में एपीआई का उत्पादन बढ़ाने, वैकल्पिक आयात स्रोत विकसित करने और जरूरी कच्चे माल का पर्याप्त भंडार तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। सरकार को विशेष रूप से लघु एवं मध्यम दवा कंपनियों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सस्ती कार्यशील पूंजी, कच्चे माल की उपलब्धता और परिवहन लागत में राहत देने के उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। दवा उत्पादन में किसी भी प्रकार की बाधा अंततः दवाओं की उपलब्धता और कीमतों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए उद्योग को राहत देना केवल कारोबारी हितों का विषय नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। दूर पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष भारत को यह चेतावनी दे रहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी समय गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकती है। भारत को दवा उत्पादन में अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना होगा। युद्ध कब समाप्त होगा, यह भारत के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव से देश के उद्योग, श्रमिकों और मरीजों को बचाने की तैयारी करना सरकार और उद्योग दोनों की जिम्मेदारी है। दवा उद्योग की मजबूती ही देश की स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूती है।

पेज 1 का शेष

सिंहस्थ कुंभ 2027...

कुंभमेले का मंगलमय निमंत्रण माना गया।

सिंहस्थ कुंभपर्व: श्रद्धा और आस्था का महासंगम

सिंहस्थ कुंभपर्व केवल बारह वर्षों में आयोजित होने वाला धार्मिक मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, संत परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महासंगम है। इसमें अलग-अलग भाषा, क्षेत्र और संप्रदायों के लोग एक ही श्रद्धाभाव से जुड़ते हैं। गोदावरी के तट पर फहराई गई धर्मध्वजा हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को वर्तमान पीढ़ी से जोड़ने का प्रतीक बनी। इस समारोह ने संत परंपरा और सिंहस्थ की ऐतिहासिक धार्मिक विरासत को एक बार फिर जीवंत किया।

नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ की तैयारियों को मिला नया उत्साह

राष्ट्रपति के हाथों धर्मध्वजारोहण के साथ आगामी नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेले की तैयारियों को भी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नई गति मिली है। देश-विदेश से आने वाले लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए नासिक और त्र्यंबकेश्वर में व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है। पायाभूत सुविधाओं, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को लेकर विभिन्न सरकारी विभाग नियोजनबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। प्राचीन धार्मिक परंपराओं की पवित्रता बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो।

धर्मध्वज पर अंकित शुभचिह्नों का विशेष महत्व

सिंहस्थ धर्मध्वज पर विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक अंकित हैं। अमृतकुंभ को अमरत्व, मुक्ति और दैवी शक्ति का प्रतीक माना गया है। ॐकार सकारात्मकता, संपूर्ण ब्रह्मांड और सर्वव्यापकता का संदेश देता है, जबकि 'श्री' अक्षर विजय और मंगल का प्रतीक है। ध्वज पर अंकित 12 रेशमी गोंडे सामाजिक एकता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक माने गए हैं। एक घंटा और तीन घुंघरू नाद तथा ब्रह्मनाद का संकेत देते हैं। ध्वज के दूसरी ओर गोदावरी के वाहन माने जाने वाले मगर के साथ सूर्य और चंद्र के शुभचिह्न भी अंकित हैं। रामतीर्थ पर संपन्न इस समारोह ने नासिक के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव में एक नया अध्याय जोड़ा। गोदावरी के पवित्र तट पर फहराई गई भगवा धर्मध्वजा ने बारह वर्षों से प्रतीक्षित सिंहस्थ कुंभपर्व के आगमन का संदेश दिया। संतों की परंपरा, श्रद्धालुओं की आस्था और आगामी महापर्व की तैयारियों के बीच यह आयोजन नासिक के इतिहास में एक यादगार अवसर बन गया।

महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में...

मामलों में कुल 3,424 रिपोर्ट दाखिल की गई हैं। इन मामलों में 2.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि 62.62 लाख रुपये की वसूली की गई है। मत्स्य संसाधनों के संरक्षण, कानूनी मछली पकड़ने की पद्धतियों को प्रोत्साहन और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विभाग की नियमित गश्त, विशेष दस्तों की निगरानी और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने सभी मछुआरों से लागू कानूनों और नियमों का पालन करने तथा कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की है।

दो गश्ती नौकाओं और नौ ड्रोन की खरीद का प्रस्ताव

मत्स्य व्यवसाय एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने कहा कि समुद्र में अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए मत्स्य व्यवसाय विभाग की कार्रवाई मछुआरों के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। इस विभागीय व्यवस्था ने बेहतरीन काम किया है और कानूनी तरीके से मछली पकड़ने वाले मछुआरों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार के पास दो गश्ती नौकाओं और नौ ड्रोन की खरीद का प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही यह व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे समुद्र में निगरानी और कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी।

महाराष्ट्र में चारा संकट से...

उपलब्ध चारे का इस्तेमाल केवल पशुओं के भोजन के लिए किया जाएगा। पैकेजिंग, जैव ईंधन और बिजली उत्पादन जैसे अन्य कार्यों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। सूखे की स्थिति में राज्य का चारा दूसरे राज्यों में भेजने पर भी कानूनी रोक लगाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी जिलों से चारे की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

चारा शिविरों की डिजिटल निगरानी

चारा शिविरों के पारदर्शी संचालन के लिए राज्यस्तरीय ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। इसमें पशुओं का पंजीकरण, दैनिक उपस्थिति, चारे का वितरण, पानी, पशु चिकित्सा सेवाओं और खर्च का रिकॉर्ड रहेगा। बायोमेट्रिक या क्यूआर कोड से उपस्थिति, भारत पशुधन प्रणाली के जरिए पंजीकरण का सत्यापन और 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने की योजना है। चारा शिविरों के संचालन के लिए पालकमंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित की जाएगी। स्थानीय परिस्थितियों, पशुधन की संख्या और चारे-पानी की उपलब्धता के आधार पर शिविर शुरू करने का निर्णय होगा।

सहकारी संस्थाओं और CSR की भी मदद

चारा प्रबंधन में चीनी मिलों, दुग्ध सहकारी संस्थाओं, गोशालाओं, स्वयंसेवी संगठनों और किसान उत्पादक कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। चीनी मिलों से गन्ने के पत्ते, बगास और शीरा उपलब्ध कराने की योजना है। चारा उत्पादन के लिए रियायती दर पर बिजली देने तथा चारा शिविरों में पानी, स्वच्छता और मशीनों की व्यवस्था के लिए CSR निधि का उपयोग करने की सिफारिश भी की गई है। पशुसंवर्धन विभाग जिलावार चारा उपलब्धता का आकलन कर साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेगा। पशुओं के स्वास्थ्य और चारे की गुणवत्ता की भी जांच होगी।

मध्यप्रदेश: गौरव से आगे, जनकल्याण की कसौटी तक

हेमेन्द्र क्षीरसागर

1 नवंबर मध्यप्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि है। वर्ष 1956 को इसी तिथि में राज्यों के पुनर्गठन के साथ मध्यप्रदेश अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद इसका वर्तमान स्वरूप बना। स्थापना दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा, उपलब्धियों, स्मरण और शेष चुनौतियों के आकलन का समय भी है। भारत के मध्यभाग में स्थित मध्यप्रदेश देश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमाएँ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से मिलती हैं।

केंद्रीय भौगोलिक स्थिति इसे सड़क, रेल, व्यापार और अंतरराज्यीय संपर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। नर्मदा घाटी, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ तथा चंबल, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल जैसे भौगोलिक-सांस्कृतिक क्षेत्र प्रदेश की विविधता को दर्शाते हैं। देश के हृदय में मध्यप्रदेश अपनी ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता, वन संपदा और कृषि क्षमता के लिए विशिष्ट पहचान रखता है। सांची, खजुराहो और भीमबेटका जैसे विश्वविख्यात धरोहर स्थल, उज्जैन की धार्मिक परंपरा। नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल ताप्ती, सोन, वैनगंगा सहित प्रमुख नदियाँ इसकी पहचान को समृद्ध बनाती हैं। गोंड, बैगा, भील और अन्य जनजातीय समुदायों की संस्कृति भी प्रदेश की अमूल्य विरासत है। इस धरोहर का संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ पर्यटन का विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के लिए देश में विशिष्ट स्थान रखता है। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, वन विहार, संजय, कूनो और अन्य राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश की प्राकृतिक संपदा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। चीता व जंगली



भैंसा पुनर्स्थापना, बाघ संरक्षण, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास। पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से इनका विशेष महत्व है। ये उद्यान प्रकृति पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं।

कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। धान, गेहूँ, सोयाबीन, दलहन और तिलहन के उत्पादन के साथ किसानों को उचित मूल्य। भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार की बेहतर सुविधाएँ देना आवश्यक है। उद्योग, पर्यटन, लघु उद्यम और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर रोजगार के स्थायी अवसर तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए युवाओं को रोजगारपरक कौशल और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। विकास की दूसरी बड़ी कसौटी शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय संतुलन है। महानगरों के साथ ग्रामीण एवं जनजातीय अंचलों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ उपचार, पेयजल, सड़क और संचार सुविधाएँ सुनिश्चित होनी चाहिए। बालाघाट जैसे जिलों में कृषि, वनोपज, खनिज और पर्यटन की संभावनाओं का उपयोग स्थानीय आजीविका तथा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। योजनाओं की सफलता घोषणाओं या बजट तक सीमित नहीं, बल्कि उनके परिणामों से तय होती है। पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवाएँ, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और नागरिकों की भागीदारी विकास को प्रभावी बनाते हैं। जल संरक्षण, वनों की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी आवश्यक है। ताकि आर्थिक प्रगति पर्यावरण की कीमत पर न हो। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस हमें गौरव के साथ आत्ममंथन का संदेश देता है। प्रदेश की वास्तविक समृद्धि तभी सुनिश्चित होगी। जब किसान को उपज का उचित मूल्य, युवा को रोजगार, महिलाओं को समान अवसर। प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएँ मिलें। मध्यप्रदेश की प्रगति का सही पैमाना केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है। यही स्थापना दिवस का सार्थक संकल्प और समृद्ध भविष्य की आधारशिला है। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।



मेष राशि: इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए सौदे लाभदायक साबित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह आर्थिक मामलों में अनुकूल रह सकता है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है। व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है।

मिथुन राशि: इस सप्ताह आपके सामने नए अवसर आ सकते हैं। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को सकारात्मक सूचना मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और बातचीत की क्षमता से लाभ होगा। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम मिलेगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें। व्यापार में किसी बड़े फैसले से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद होगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान दें।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता और सम्मान लेकर आ सकता है। नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। कारोबार में विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम जरूरी है।

कन्या राशि: इस सप्ताह आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नौकरी में लंबे समय से अटके काम पूरे होने के संकेत हैं। कार्यस्थल पर आपके सुझावों को महत्व मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन उधार देने से बचें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। घर में जरूरी कामों पर खर्च हो सकता है।

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए सप्ताह नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापारियों को नए ग्राहक और लाभदायक सौदे मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन दिखावे पर खर्च न करें। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है।

वृश्चिक राशि: इस सप्ताह आपको अपने काम और निर्णयों में सावधानी रखनी होगी। नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी। व्यापार में पुराने संपर्क लाभ पहुंचा सकते हैं। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। परिवार में छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है। बातचीत से समस्या सुलझाने का प्रयास करें।

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर में प्रगति के संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा लोगों को नई परियोजना या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। दूर के संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कामकाज की व्यस्तता लेकर आएगा। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी मेहनत और अनुशासन से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। व्यापार में धीरे-धीरे लाभ बढ़ेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। संपत्ति संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक कार्यों और नई योजनाओं के लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी में आपके नए विचारों को सराहना मिल सकती है। तकनीक और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ होगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी।

मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए सप्ताह सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी। कारोबार में नया समझौता लाभदायक साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बचत बढ़ाने का अवसर मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान दें।

एल.आई.सी



भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।
-भारत सिंह
मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जांचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए सुबह से शाम तक की खबरे के अंतर्गत समाचारपत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाए या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

किसानों को ग्रीन अमोनिया से सस्ती खाद की उम्मीद



सौरभ वार्ष्णेय

भारतीय कृषि लंबे समय से बढ़ती लागत और घटती आमदनी की चुनौती व पुरानी रुढिवादी तकनीक से जूझ रही है। डीजल, बिजली, बीज, कीटनाशक और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि ने किसानों के सामने आर्थिक संकट को और गहरा किया है। खेती की लागत में उर्वरकों की हिस्सेदारी भी काफी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से यूरिया की उपलब्धता और उसकी कीमत किसानों के लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशना एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा सकती है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो आने वाले समय में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है। हालांकि, इस पहल की वास्तविक सफलता केवल तकनीकी प्रयोग तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका लाभ खेतों में काम करने वाले किसानों तक पहुंचना भी जरूरी है। किसानों के लिए खुश खबरी आई है कि सरकार छह राज्यों में लगभग 10 हजार एकड़ भूमि पर ग्रीन अमोनिया के उपयोग का परीक्षण कर रही है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि पारंपरिक नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल कितना प्रभावी और किफायती हो सकता है। ग्रीन अमोनिया का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से तैयार हाइड्रोजन के माध्यम से किया जाता है। इसके विपरीत परंपरागत अमोनिया उत्पादन में मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की अधिक खपत के साथ कार्बन उत्सर्जन भी होता है। इसलिए ग्रीन अमोनिया को न केवल कृषि की लागत कम करने, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक संभावनाशील विकल्प माना जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी के अनुसार, अमोनिया को सीधे मिट्टी में डालने से उर्वरक की लागत मौजूदा स्तर से लगभग एक-तिहाई तक घट सकती है। यदि यह अनुमान व्यावहारिक रूप से सही साबित होता है तो खाद उत्पादन और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल भी है कि उत्पादन लागत में संभावित कमी का लाभ किसानों को किस रूप में मिलेगा? क्या इससे यूरिया की खुदरा कीमत घटेगी, या सरकार की सब्सिडी का बोझ कम होगा?

इन सवालों का जवाब परीक्षण के परिणाम और सरकार की नीतिगत व्यवस्था से ही मिलेगा। दरअसल, भारत में यूरिया केवल एक औद्योगिक उत्पाद नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। देश में बड़ी संख्या में किसान नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया पर निर्भर हैं। सरकार किसानों को सस्ती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए भारी सब्सिडी देती है। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर उर्वरक क्षेत्र पर पड़ता है। भारत को उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल और गैस की उपलब्धता के मामले में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा आधारित अमोनिया का विकल्प देश की आयात निर्भरता कम करने में भी सहायक हो सकता है। हालांकि, ग्रीन अमोनिया को यूरिया का सीधा और तत्काल विकल्प मान लेना जल्दबाजी होगी। अमोनिया एक प्रभावी नाइट्रोजन स्रोत है, लेकिन इसका सुरक्षित भंडारण, परिवहन और खेतों में उपयोग विशेष तकनीकी सावधानी की मांग करता है। यह एक विषाक्त रसायन है और इसके रिसाव से मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

इसलिए किसानों को इसके इस्तेमाल की उचित जानकारी, सुरक्षा उपकरण और आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त मिट्टी की प्रकृति, फसल की जरूरत, मौसम और सिंचाई की परिस्थितियों के अनुसार इसके प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ग्रीन अमोनिया की उत्पादन लागत है। नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन तैयार करने और उसके माध्यम से अमोनिया बनाने के लिए बड़े निवेश, आधुनिक तकनीक और पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत होती है। जब तक इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नहीं होगा, तब तक किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरी तरह हासिल करना आसान नहीं होगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस तकनीक के विकास का आर्थिक बोझ अंततः किसानों पर न पड़े। भारत में कृषि सुधारों की चर्चा अक्सर नई तकनीक और आधुनिक उत्पादन प्रणालियों तक सीमित रह जाती है, जबकि किसान की सबसे बड़ी चिंता उसकी लागत और उपज का उचित मूल्य है। ग्रीन अमोनिया की पहल को भी इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

यदि इससे उर्वरकों की कीमत कम होती है, मिट्टी की सेहत बेहतर रहती है और पर्यावरण को नुकसान घटता है तो यह कृषि क्षेत्र के लिए दूरगामी परिवर्तन साबित हो सकता है। लेकिन केवल उत्पादन लागत में कमी का दावा पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पारदर्शी मूल्य



निर्धारण, वितरण व्यवस्था और किसानों तक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर भी ध्यान देना जरूरी है। अत्यधिक यूरिया के इस्तेमाल से मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ता है और कृषि भूमि की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

इसलिए ग्रीन अमोनिया को केवल सस्ती खाद के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि टिकाऊ कृषि व्यवस्था के व्यापक हिस्से के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जैविक खाद, नैनो उर्वरक, प्राकृतिक खेती और मिट्टी परीक्षण जैसी व्यवस्थाओं के साथ इसका संतुलित समन्वय जरूरी है। निस्संदेह, ग्रीन अमोनिया की दिशा में सरकार का प्रयोग भविष्य की कृषि के लिए उम्मीद जगाता है। लेकिन किसानों को ऐसी योजनाओं के परिणामों के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना चाहिए। सरकार को परीक्षण के नतीजे सार्वजनिक करने, उत्पादन लागत का वास्तविक आकलन करने और किसानों को मिलने वाले संभावित लाभ का स्पष्ट खाका तैयार करना चाहिए। कृषि प्रधान देश में तकनीकी नवाचार की सार्थकता तभी है, जब उसका लाभ खेत और किसान तक पहुंचे। आखिरकार, ग्रीन अमोनिया का उद्देश्य केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि किसान की जेब पर पडने वाला बोझ कम करना भी होना चाहिए। सस्ती खाद, स्वस्थ मिट्टी और खुशहाल किसान ही इस नई पहल की वास्तविक सफलता का पैमाना होंगे।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 12वां आरोपी गिरफ्तार 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत

संवाददाता

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12वें आरोपी अमन को हरियाणा के सोनीपत जिले के रोहना गांव से गिरफ्तार किया है। शनिवार को मुंबई की विशेष अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को पकड़ा था। जांचकर्ताओं के मुताबिक, अमन इस मामले में पहले गिरफ्तार किए जा चुके आरोपी कुणाल का दोस्त है। पुलिस फायरिंग की घटना से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन में उसकी भूमिका की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अमन ने क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन लेन-देन कर अपने सह-आरोपियों को करीब 45 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी थी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह रकम फायरिंग की कथित साजिश से जुड़ी थी या नहीं। बचाव पक्ष के वकील अजिंक्य मिरगल के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने आरोपी की 15 दिन की पुलिस



हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे 6 नवंबर तक हिरासत में रखने का आदेश दिया। वकील ने कहा कि आरोपी को सोनीपत में गिरफ्तार करने के बाद तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया था। उन्होंने यह भी दलील दी कि कथित ऑनलाइन लेन-देन की जानकारी बैंकिंग संस्थानों और रिकॉर्ड से हासिल की जा सकती है। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में उसकी कथित भूमिका की जांच जारी है।

निर्माण स्थलों से सरिया चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पांच आरोपी गिरफ्तार

इंद्र यादव

मुंबई। मुंबई के निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों से लोहे की सरिया चोरी करने वाले संगठित गिरोह का अपराध शाखा यूनिट-7 ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 1 करोड़ 64 लाख 25 हजार 990 रुपये का माल जब्त किया है। इसमें 54 लाख 25 हजार 990 रुपये की लोहे की सरिया, तीन ट्रक और एक अशोक लेलैंड टेम्पो शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपसी साजिश के तहत पैसों के बदले ट्रेलरों की मदद से निर्माण स्थलों से सरिया चोरी कर रहे हैं। इसके बाद विशेष टीम गठित कर निगरानी और कार्रवाई शुरू की गई। 28 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 5:55 बजे घाटकोपर पूर्व में पूर्व द्रुतगति महामार्ग पर ठाणे से मुंबई की ओर जाने वाली सड़क के किनारे हायवे सुविधा शौचालय के पास पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। उनके पास से 38,380 किलो सरिया बरामद हुई, जिसकी कीमत 23 लाख 2 हजार 800 रुपये बताई गई है। जांच में चूनाभट्टी स्थित जुगल इंडस्ट्रियल एस्टेट से



भी इसी गिरोह द्वारा 1 लाख 4 हजार 750 किलो सरिया चोरी किए जाने का मामला सामने आया। इसकी कीमत 31 लाख 23 हजार 190 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने दोनों मामलों में चोरी का माल बरामद कर पंतनगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच अपराध शाखा यूनिट-7 कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) अनिल कुंभारे, अपर पुलिस आयुक्त कृष्णकांत उपाध्याय, पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले और सहायक पुलिस आयुक्त धर्मपाल बनसोडे के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी का माल खरीदने वालों की तलाश कर रही है।

मुंबई में बनेगा व्यंग्यचित्रकारों की कला का प्रदर्शनी कक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिया भरोसा

संवाददाता

मुंबई। मुंबई में व्यंग्यचित्रकारों की कला को एक जगह सहेजने और लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रदर्शनी कक्ष बनाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह काम सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। दादर स्थित स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक सभागृह में व्यंग्यचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी द्वारा संपादित और ग्रंथाली प्रकाशन की ओर से प्रकाशित पुस्तक 'महाराष्ट्राच्या हास्यरेषा' के विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ग्रंथाली प्रकाशन के न्यासी सुदेश हिंगलासपूरकर और पुस्तक के संपादक प्रशांत कुलकर्णी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि व्यंग्य चित्रकला ऐसी कला है, जिसमें बिना कुछ बोले भी बड़ी बात आसानी से कही जा सकती है। मराठी व्यंग्यचित्रकारों ने अपने चित्रों के जरिए समय-समय पर समाज और राजनीति की घटनाओं के साथ-साथ कई विरोधाभासों को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि व्यंग्यचित्र किसी व्यक्ति के पूरे



व्यक्तित्व को कुछ रेखाओं में दिखाने की ताकत रखते हैं। महाराष्ट्र में इस कला की पुरानी परंपरा रही है और 'महाराष्ट्राच्या हास्यरेषा' जैसी पुस्तक इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि व्यंग्यचित्र को समझने के लिए उसकी रेखाओं के बीच छिपे अर्थ को समझना जरूरी है। उन्होंने व्यंग्यचित्रकार के रूप में अपने अनुभव और 'फटकारे' पुस्तक के निर्माण से जुड़ी बातें भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि व्यंग्यचित्रकार समाज की गलतियों और विसंगतियों को अपने चित्रों के जरिए सामने लाता है। राज ठाकरे ने व्यंग्यचित्र बनाते समय रेखाओं की अहमियत, स्वाभिमान और विषय की सही समझ पर जोर दिया। उन्होंने पुराने व्यंग्यचित्रकारों से जुड़ी यादें भी साझा कीं। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने पुस्तक तैयार करने में प्रशांत कुलकर्णी और ग्रंथाली के सदस्यों की मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुस्तक में संकलित पुराने और ऐतिहासिक व्यंग्यचित्र महाराष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण धरोहर हैं। उन्होंने वरिष्ठ व्यंग्यचित्रकार शि.द.फडणीस के योगदान का उल्लेख करते हुए बताया कि पुणे विश्वविद्यालय में उनके नाम से अध्ययन केंद्र शुरू करने का काम चल रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यंग्यचित्रकार और कला प्रेमी मौजूद रहे।

नालासोपारा में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, दो सगे भाई गिरफ्तार

संवाददाता

पालघर। नालासोपारा पूर्व में 15 वर्षीय किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म और फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पेल्हार पुलिस ने इस मामले में दो सगे भाइयों अमन नतीफ शेख (24) और अरबाज शेख (30) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों को वसई की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया गया। दर्ज एफआईआर के मुताबिक, घटना 27 अक्टूबर को सुबह करीब 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच गावदेवी मंदिर के पास स्थित एक कपड़े की दुकान में हुई। आरोप है कि दुकान के अंदर दोनों भाइयों ने किशोरी के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद उसे धमकी दी गई कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसकी तस्वीरें और वीडियो उसकी मां को भेज दिए जाएंगे और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। मामले में 30 अक्टूबर की देर शाम पेल्हार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 65(1), 70(2), 351(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 व 8 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने देर रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच पीएसआई सचिन शिंदे के नेतृत्व में की जा रही है। पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। नाबालिग से जुड़े इस गंभीर मामले में पीड़िता की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। आरोपों की सच्चाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

महाराष्ट्र शासन
कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा. बां.) विभाग,
प्रशासकीय इमारत, १ ला मजला, भवन्स कॉलेज जवळ, दादाभाई रोड, अंधेरी (प.), मुंबई- ४०००५८.
E-mail-northmumbai.ee@mahapwd.com दुरध्वनी क्रमांक .०२२-२६२३१९६४ फॅक्स - २६२०५७८८

निविदा सुचना क्र. ३५ सन २०२६-२७

महाराष्ट्र राज्यपालांच्या वतीने कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, दादाभाई मार्ग, भवन्स कॉलेज जवळ अंधेरी (प) मुंबई-४०००५८ (दुरध्वनी/फॅक्स क्रमांक- २६२३१९६४/२६२०५७८८) महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडुन योग्य त्या वर्गातील नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडुन खालील कामाकरीता ब-१ नमुन्यातील निविदा मागवित आहेत. निविदा कागदपत्र दिनांक- ३०/१०/२०२६ ते दिनांक- ०६/११/२०२६ कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयात उपलब्ध असतील. तसेच दिनांक- ०९/११/२०२६ दुपारी १७/- वाजेपर्यंत निविदा स्विकारण्यात येतील व शक्य झाल्यास त्याच दीवशी निविदा उघडण्यात येतील निविदा स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, मुंबई यांनी राखून ठेवला आहे.

अ.क्र	कामाचे नांव	अंदाजित रक्कम
१	कीरकोळ दुरुस्ती अंतर्गत शासकिय वसाहत वांद्रे पुर्व येथील इमारत क्र ब-१५८ ते ब-१६९ व ब-१७० ते ब-१७९ मधील दैनंदिन साफसफाई करणे.	रु.८०२३५४/-
२	कीरकोळ दुरुस्ती अंतर्गत शासकिय वसाहत वांद्रे पुर्व येथील इमारत क्र य-७ ते य-८ मधील दैनंदिन साफसफाई करणे.	रु.८००७९३/-
३	बांद्रा (सा. बां.) उप विभाग क्र.०२ अंतर्गत बांद्रा शासकीय वसाहतीतील इमारत क्र. बी-४ मधील दैनंदिन साफसफाई, केरकचरा काढणे इत्यादी हाऊसकीपिंगची कामे करणे.	रु.७००७०३/-
४	बांद्रा (सा. बां.) उप विभाग क्र.०२ अंतर्गत बांद्रा शासकीय वसाहतीतील इमारत क्र. ए-३ मधील दैनंदिन साफसफाई, केरकचरा काढणे इत्यादी हाऊसकीपिंगची कामे करणे.	रु.८४३५५८/-

निविदा स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता , उत्तर मुंबई(सा.बां) विभाग, अंधेरी (प.) मुंबई ५८.यांनी राखून ठेवला आहे.अट असलेली निविदा स्विकारली जाणार नाही.

जा.क्र.काअ/उमुंवि/भांडार/ ६३६४
कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय,
उत्तर मुंबई(सा.बां) विभाग,
प्रशासकीय इमारत, १ ला मजला,
भवन्स कॉलेजजवळ, दादाभाई मार्ग,
अंधेरी (प.) मुंबई ५८.
दिनांक :- 26 OCT 2026

कार्यकारी अभियंता,
उत्तर मुंबई(सा.बां) विभाग,
अंधेरी (प.) मुंबई ५८.

डीजीआईपीआरः आरओसी 2026-27/क्र 5/सी 3501

MPSC की नौ परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए आयोग गठित

पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में जांच, परीक्षार्थी 16 नवंबर तक शपथपत्र के साथ शिकायतें जमा कर सकेंगे

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र या उत्तरतालिका लीक होने के कथित मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार ने जांच आयोग गठित किया है। आयोग ने परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों, संबंधित संस्थाओं और अन्य लोगों से 16 नवंबर 2026 तक शपथपत्र के साथ अपना पक्ष और शिकायतें प्रस्तुत करने की अपील की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। आयोग नौ परीक्षाओं से जुड़े कथित पेपर लीक और उत्तरतालिका संबंधी मामलों की जांच करेगा। इनमें औषध निरीक्षक परीक्षा समूह-ब 2025, महाराष्ट्र समूह-ब और समूह-क की संयुक्त पूर्व एवं मुख्य परीक्षाएं 2025, महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024, खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 तथा सिविल और विद्युत अभियांत्रिकी सेवा की मुख्य



परीक्षाएं 2025 शामिल हैं।

शिकायत के साथ पहचान पत्र और दस्तावेज जरूरी

आयोग ने कहा है कि शिकायतें मराठी या अंग्रेजी भाषा में शपथपत्र के रूप में प्रस्तुत की जाएं। इसके साथ वैध पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां लगाना अनिवार्य है। शिकायतें आयोग के कार्यालय, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन, कक्ष संख्या 201, दूसरी मंजिल, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 में जमा की जा सकती हैं। इसकी एक प्रति ई-मेल complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। आयोग के सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे के अनुसार, प्राप्त शिकायतों, शपथपत्रों और दस्तावेजों को गोपनीय रखा जाएगा।

शिकायतों की छानबीन के बाद संबंधित व्यक्तियों को गवाह के रूप में बुलाने का निर्णय आयोग करेगा।

डाक विभाग की नई पहल: हर महीने के पहले शुक्रवार को लगेगी 'मासिक अदालत'

संवाददाता

मुंबई। डाक सेवाएं देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। समाज के हर वर्ग तक पहुंच रखने वाला डाक विभाग अब ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए नई पहल शुरू कर रहा है। शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक मजबूत और सुलभ बनाने के उद्देश्य से विभाग ने हर महीने के पहले शुक्रवार को 'मासिक अदालत दिवस' आयोजित करने का निर्णय लिया है।

एक ही दिन चार प्रकार की अदालतें होंगी आयोजित

इस पहल के तहत हर महीने के पहले शुक्रवार को स्टाफ अदालत, ग्रामीण डाक सेवक (GDS) अदालत, पेंशन अदालत और डाक अदालत आयोजित की जाएंगी। ये सभी अदालतें सर्कल, क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर एक साथ लगेंगी। इसका उद्देश्य डाक सेवाओं, कर्मचारियों, ग्रामीण डाक सेवकों और पेंशनभोगियों से



जुड़ी शिकायतों का प्रभावी और समयबद्ध समाधान करना है।

6 नवंबर को सुबह 11:45 बजे पहली अदालत

महाराष्ट्र सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय की ओर से पहली 'मासिक अदालत दिवस' शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को सुबह 11:45 बजे आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई जीपीओ, दूसरी मंजिल, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400001 में होगा।

4 नवंबर तक जमा कर सकते हैं शिकायतें

महाराष्ट्र और गोवा को कवर करने वाले महाराष्ट्र सर्कल से संबंधित शिकायतें 4 नवंबर 2026 तक संबंधित ग्रुप अधिकारियों के पास भेजी जा सकती हैं। इनमें स्टाफ से जुड़े मामले, ग्रामीण डाक सेवकों की शिकायतें, पेंशन संबंधी समस्याएं और डाक सेवाओं से संबंधित मामले शामिल होंगे। आवेदन में शिकायत का पूरा विवरण, संबंधित सहायक दस्तावेज और उस कार्यालय या प्राधिकारी की जानकारी देना आवश्यक होगा, जहां पहले शिकायत भेजी गई थी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया और माध्यम से संबंधित अधिकारियों के पास अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।

डाक विभाग की इस पहल का उद्देश्य शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ और जवाबदेह बनाना है। विभाग को उम्मीद है कि मासिक अदालतों के माध्यम से नागरिकों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने रखने और उनका समय पर समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

इंदापुर में हाईवे निर्माण के दौरान मिट्टी का ढेर गिरा एक मजदूर की मौत और एक घायल

संवाददाता

पालघर। महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर तालुका स्थित राजवाड़ी गांव में पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर के पास साइड पट्टी के भराव का काम चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी और मुरुम का ढेर अचानक ढह गया। इस हादसे में एक मजदूर की दबकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया। दुर्घटना शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 10 बजे हुई।

एक मजदूर ने सूझबूझ से बचाई जान

हादसे के समय घटनास्थल पर तीन मजदूर काम कर रहे थे। मिट्टी-मुरुम का ढेर गिरते ही एक मजदूर ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को सुरक्षित बचा लिया। वहीं, बाकी दो मजदूरों में से एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि



दूसरे मजदूर की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। घायल मजदूर को तत्काल बाहर निकालकर इंदापुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। प्रशासन की ओर से घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस दुर्घटना पर महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घटना की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हर भारतीय के दिल में रखते हैं विशेष स्थान: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

संवाददाता

मुंबई। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का हर भारतीय के मन में विशेष स्थान है। यह क्षेत्र भारत का मुकुट है। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का अर्थ विविधताओं के बीच दिलों, मनों और विचारों की एकता है। यह बात राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कही। केंद्र सरकार के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के तहत लोकभवन में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख स्थापना दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर को निर्धारित स्थापना दिवस राष्ट्रपति के नासिक दौरे के कारण एक दिन पहले आयोजित किया गया।

विविधता ही भारतीय एकता की पहचान

राज्यपाल ने कहा कि विविधता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता स्थापित करना 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। देश के प्रत्येक राज्य की भाषा, संस्कृति, परंपराएं और कला अलग-अलग हैं, लेकिन इन्हीं विविधताओं से भारतीय सभ्यता और



एकता की पहचान बनती है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हस्तकला, नृत्य और परंपराएं देश के गौरव में वृद्धि करती हैं।

विद्यार्थियों से विभिन्न राज्यों की संस्कृति जानने का आह्वान

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने लोगों से अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों से देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, इतिहास, खान-पान और परंपराओं के बारे में जानने की अपील की।

कलाकारों और विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम

कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कलाकारों के साथ बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अभ्युदय नगर, कालाचौकी स्थित स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर राज्यपाल के हाथों विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों, कलाकारों और विद्यार्थियों के साथ डोगरा समाज, कश्मीरी पंडित एसोसिएशन, आईआईटी मुंबई तथा 'युवा संगम-7' के प्रतिनिधियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, जीएचआरटी इंटरनेशनल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एच. आर. रहमा, आईआईटी मुंबई के उपनिदेशक प्रो. मिलिंद अत्रे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका की शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजश्री शिरवाडकर और पूर्व महापौर श्रद्धा जाधव सहित 'युवा संगम-7' के सदस्य, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नागरिक, कश्मीरी पंडित एसोसिएशन के प्रतिनिधि, कलाकार तथा विद्यार्थी उपस्थित थे।

मुंबई के शिवड़ी और वरली किलों के संरक्षण को मिलेगी गति

वैभव संगोपन योजना के तहत RPG फाउंडेशन ने शिवड़ी किले को लिया गोद, वरली किले के संरक्षण पर भी जोर

संवाददाता

मुंबई। मुंबई की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोक परंपराओं की विरासत को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र शासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग की वैभव संगोपन योजना के तहत संरक्षण प्रयासों को गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विशेष सहयोग से विभाग की मंजूरी के बाद RPG फाउंडेशन ने ऐतिहासिक शिवड़ी किले को संरक्षण के लिए गोद लिया है। इसी योजना के माध्यम से वरली किले के संरक्षण को भी आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। RPG फाउंडेशन की पहल 'द हेरिटेज प्रोजेक्ट' के तहत बाणगंगा, वरली कोलीवाड़ा और शिवड़ी किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए अनुसंधान, जनभागीदारी, सांस्कृतिक गतिविधियों, बुनियादी सुविधाओं के विकास और महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फाउंडेशन के अनुसार, इस पहल के माध्यम से अब तक 50 हजार से अधिक नागरिकों तक पहुंच बनाई गई है और 270 से अधिक महिलाओं को आजीविका तथा उद्यमिता के लिए सहयोग दिया गया है। मुंबई के पूर्वी तट पर स्थित शिवड़ी किला शहर के समुद्री इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित करने और नागरिकों तथा पर्यटकों को इसके महत्व से परिचित कराने के लिए संग्रहालय और सूचना केंद्र विकसित करने की योजना है। वहीं, वरली किले के संरक्षण के साथ वरली कोलीवाड़ा के इतिहास, परंपराओं, जीवनशैली और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।

परियोजना के तहत वरली कोलीवाड़ा में 71 से अधिक स्ट्रीट लाइटें, 30 से अधिक सूचना पट्ट और सात से अधिक सार्वजनिक भित्तिचित्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र की 120 से अधिक महिलाओं



को कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सहयोग दिया गया है। 'शेफ्स ऑफ कोलीवाड़ा' पहल के माध्यम से महिलाओं को पारंपरिक कोली खानपान संस्कृति को नई पहचान दिलाने और खाद्य महोत्सवों तथा प्रदर्शनियों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। बाणगंगा तालाब परिसर में भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस पहल के अंतर्गत 150 से अधिक महिलाओं को उद्यमिता, सिलाई और स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 500 से अधिक पर्यटकों को विभिन्न कार्यक्रमों और अनुभवात्मक गतिविधियों के माध्यम से इस विरासत स्थल से जोड़ा गया है।

विरासत संरक्षण की इस पहल का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों की परंपराओं, कलाओं, खानपान और जीवनशैली को भी संरक्षित करना है। इसके साथ नागरिक सुविधाओं में सुधार, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, स्थानीय रोजगार सृजन और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि मुंबई की समृद्ध विरासत का संरक्षण समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ सके।

झांसी के 2.01 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 40.31 करोड़ रुपये



देवेश प्रताप सिंह राठौर

झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत झांसी जिले के 2,01,585 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 40 करोड़ 31 लाख रुपये भेजे गए। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विकास भवन सभागार सहित जिले के सभी विकासखंड सभागारों, पंचायत भवनों, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, कृषि मंडियों, किसान उत्पादक संगठनों के कार्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में किया गया। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड ने की। उन्होंने जिले के सभी लाभार्थी किसानों को बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2019 से यह योजना लगातार चल रही है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल छह हजार रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं। प्रत्येक चार महीने के अंतराल पर दो हजार रुपये की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचती है। उन्होंने कहा कि यह राशि किसानों की रोजमर्रा की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है और इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन और किस्त जारी होने का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर संयुक्त कृषि निदेशक डॉ. वी.वी. दुबे, उप कृषि निदेशक बुद्धदेव दुबे, विषय वस्तु विशेषज्ञ दीपक कुशवाहा, लल्ला सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार सहित कृषि विभाग के अधिकारी और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।

काशी में गंगा के पानी में मिला माइक्रोप्लास्टिक, सरायमोहना घाट पर सबसे ज्यादा कण

संवाददाता



वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी में गंगा के पानी में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की मौजूदगी सामने आई है। अलग-अलग घाटों से लिए गए पानी के नमूनों की जांच में सरायमोहना घाट पर एक लीटर पानी में माइक्रोप्लास्टिक के सात कण मिले हैं। दशाश्वमेध घाट पर चार से पांच, मार्कंडेय महादेव घाट पर दो से तीन और गड़वाघाट पर एक से 1.8 कण प्रति लीटर दर्ज किए गए। शूलटंकेश्वर महादेव घाट पर इनकी मात्रा सबसे कम 0.5 से एक कण प्रति लीटर पाई गई। जांच के अनुसार, काशी में गंगा के पानी में औसतन 1.5 से 2.5 माइक्रोप्लास्टिक कण प्रति लीटर मौजूद हैं। बीएचयू के पर्यावरणविद डॉ. कृपा राम ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने बताया कि पांच मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। गंगा में इनकी मौजूदगी और इनके स्रोतों का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि इनका जलीय जीवन और पूरे पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। माइक्रोप्लास्टिक के खतरे को देखते हुए इसकी निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी पहल शुरू की गई है। भारत सरकार ने पिछले महीने पांच मिलीमीटर तक के माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया था। इसके बाद बृहस्पतिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के कार्यालय में निगरानी टीम की पहली बैठक हाइब्रिड तरीके से हुई। बैठक में गंगा में माइक्रोप्लास्टिक के स्रोत, उसकी मात्रा और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने पर चर्चा की गई। इस अभियान में बीएचयू और आईआईटी रुड़की सहित आठ संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं। निगरानी के तहत गंगा में प्रदूषण के प्रमुख स्थानों, माइक्रोप्लास्टिक के बहाव के रास्तों और उसके संभावित प्रभावों की पहचान की जाएगी। इसके लिए नियमित जांच की व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें।

2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा लखनऊ में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक शुरू

संवाददाता



लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का शुभारंभ अमित शाह ने किया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी, जितिन प्रसाद सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। स्वागत भाषण में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि यह बैठक केवल औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि प्रदेश में पार्टी संगठन की ताकत का आकलन करने, सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा करने और आगे की रणनीति तय करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने और प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के संकल्प के साथ जुटें। चौधरी ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 14 जुलाई 2024 को इसी सभागार में पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। संगठन की नई रचना के बाद प्रदेश कार्यसमिति की यह पहली बैठक है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ नए सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। बैठक तीन सत्रों में आयोजित की जा रही है। दूसरे सत्र में राजनीतिक एजेंडे, चुनावी तैयारियों और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही संगठन की गतिविधियों की समीक्षा कर उन क्षेत्रों और बूथों पर विशेष ध्यान देने की रणनीति बनाई जाएगी, जहां पार्टी को अपनी स्थिति मजबूत करनी है। राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, सुशासन, गरीब कल्याण और सरकार के फैसलों को प्रमुखता से रखा जाएगा। बैठक से पहले प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और प्रदेश सह-प्रभारी मेधा कुलकर्णी, अनंत ओझा तथा प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी 'जहां कमजोर, वहां ज्यादा जोर' के मंत्र के साथ काम करेगी। बैठक के लिए पंजीकरण, भोजन, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। धर्मपाल सिंह ने आयोजन को अनुशासित और व्यवस्थित बनाने के लिए टीमवर्क, पहले से तैयारी और बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया।

उन्नाव में शिव महापुराण कथा के लिए नि:शुल्क बस सेवा शुरू



संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक एनएच-31, गौरी बीघापुर, उन्नाव में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सदर विधायक पंकज गुप्ता की ओर से निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरुण सिंह के आयोजन में हो रही इस कथा में क्षेत्र के अधिक से अधिक श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकें, इसी उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। गांधी नगर तिराहा, उन्नाव पर बनाए गए निःशुल्क बस सेवा कैंप का शुभारंभ विधायक पंकज गुप्ता के पुत्र प्रखर गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने तीन बसों को हरी झंडी दिखाकर कथा स्थल के लिए रवाना किया। श्रद्धालुओं के लिए कैंप में जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। प्रखर गुप्ता ने कहा कि श्रद्धालुओं को कथा स्थल तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसलिए विधायक की ओर से यह सेवा शुरू की गई है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से कथा में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ की महिमा का श्रवण करने की अपील की।

यह निःशुल्क बस सेवा प्रतिदिन गांधी नगर तिराहा से सुबह 11 बजे कथा स्थल के लिए रवाना होगी, जबकि वापसी के लिए शाम 4 बजे से बसों की व्यवस्था रहेगी। 5 नवंबर तक कथा आयोजन की पूरी अवधि में यह सेवा जारी रहेगी।

फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 57 वर्ष की उम्र में निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

संवाददाता

'कांटे', 'शूटआउट एट लोखंडवाला' और 'काबिल' जैसी फिल्मों के निर्देशक के आकस्मिक निधन पर संजय दत्त, काजोल और सोनू सूद ने जताया दुख



मुंबई। फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात वर्सोवा पुलिस थाना क्षेत्र स्थित अपने घर में अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी और उनकी जान चली गई। उनके आकस्मिक निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। संजय गुप्ता 'कांटे', 'शूटआउट एट लोखंडवाला' और 'काबिल' जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते थे। उनके निधन पर अभिनेता संजय दत्त ने भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दोनों की पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि वे हाल ही में 'कांटे 2' को लेकर चर्चा कर रहे थे। संजय दत्त ने इसे अपने दोस्त का सपना बताते हुए कहा कि वह इस फिल्म को उनकी याद में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।

काजोल और सोनू सूद ने भी दी श्रद्धांजलि

अभिनेत्री काजोल ने संजय गुप्ता के निधन को दिल तोड़ने वाली खबर बताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अभिनेता सोनू सूद ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए कहा कि सेट पर साथ बिताए समय की यादें हमेशा उनके दिल के करीब रहेंगी। अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने फिल्म 'द मिरांडा ब्रदर्स' की शूटिंग के दौरान उनके साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने बताया कि संजय गुप्ता सेट पर और उसके बाहर हमेशा खुशमिजाज रहते थे तथा कलाकारों के साथ परिवार जैसा व्यवहार करते थे। संजय गुप्ता के निधन से फिल्म जगत ने एक ऐसे फिल्ममेकर को खो दिया है, जिनकी फिल्मों और कलाकारों के साथ उनकी दोस्ती को लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनके परिवार को इस मुश्किल समय से उबरने की ताकत देने की प्रार्थना की। अभिनेता सोनू सूद ने उन्हें याद करते हुए लिखा कि हर्षवर्धन राणे ने फिल्म 'द मिरांडा ब्रदर्स' की शूटिंग के दौरान उनके साथ बिताए समय को याद किया। उन्होंने बताया कि संजय गुप्ता सेट पर और उसके बाहर हमेशा खुशमिजाज रहते थे और शूटिंग के दौरान उन्हें तथा मीजान जाफरी को गोवा में खाने के लिए बाहर ले जाया करते थे। हर्षवर्धन ने उनके परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि इस खबर से उनका दिल टूट गया है।

रात में जगमगाते बाजार व्यापारियों के बढ़ते भरोसे की पहचान: योगी आदित्यनाथ

संवाददाता



लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में रात के समय जगमगाते बाजार और खुले व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यापारियों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि वर्ष 2017 से पहले अपराध और असुरक्षा के कारण सूर्यास्त होते ही बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां कम होने लगती थीं। देर रात तक काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर परिवारों में भी चिंता रहती थी। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने कानून-व्यवस्था में सुधार और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। आज बाजार देर रात तक खुले रहते हैं, जिससे व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने के नए अवसर मिल रहे हैं। वहीं, महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में बिना डर के काम कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और समाज की प्रगति का संकेत है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में महिला श्रम बल भागीदारी करीब 13 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगति बताते हुए कहा कि सुरक्षित माहौल के कारण प्रदेश अब 'सुरक्षा से समृद्धि' की ओर बढ़ रहा है।

'नागिन' के नए सीजन में नजर आ सकती हैं श्रुतिका अर्जुन कास्टिंग को लेकर चर्चा तेज



मुंबई। 'बिग बॉस 18' से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्रुतिका अर्जुन जल्द ही एकता कपूर के लोकप्रिय सुपरनैचुरल शो 'नागिन' में नजर आ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें शो के आगामी सीजन में एक अहम भूमिका के लिए विचार किया जा रहा है। हालांकि, अभी तक अभिनेत्री या शो के निर्माताओं की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 'नागिन' भारतीय टेलीविजन के चर्चित धारावाहिकों में शामिल है। सुपरनैचुरल कहानी, रहस्य, भावनात्मक टकराव और बदले की साजिशों के चलते इस फ्रैंचाइजी ने लंबे समय से दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाए रखी है। इसके अलग-अलग सीजन में मौनी रॉय, सुरभि ज्योति, निया शर्मा, तेजस्वी प्रकाश और प्रियंका चाहर चौधरी जैसी अभिनेत्रियां मुख्य भूमिकाओं में नजर आ चुकी हैं। 'बिग बॉस 18' में श्रुतिका अपनी बेबाक राय, ऊर्जावान अंदाज और साफगोई के कारण चर्चा में रही थीं। इस शो के बाद उनके अगले प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी है। अगर 'नागिन' में उनकी एंट्री की खबर सही साबित होती है, तो दर्शकों को उन्हें एक अलग अंदाज में देखने का मौका मिल सकता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें मुख्य भूमिका मिलेगी या कहानी में कोई अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाने का अवसर मिलेगा। आधिकारिक घोषणा होने तक श्रुतिका अर्जुन की 'नागिन' में एंट्री को लेकर चल रही चर्चाओं को अटकल ही माना जा रहा है।

बीडा में बनेगा डेटा सेंटर क्लस्टर, बुंदेलखंड को मिलेगा डिजिटल और औद्योगिक विकास का नया आधार

संवाददाता

झांसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र में प्रस्तावित डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना और विकास को लेकर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद सीईओ ने बीडा के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर परियोजना की संभावनाओं और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया।

निवेश, रोजगार और डिजिटल अवसंरचना पर हुई चर्चा

बैठक में बीडा के अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे, सीईओ संजय खत्री, जिलाधिकारी गौरांग राठी, एसीईओ प्रवीण वर्मा, सीजीएम अरविंद कुमार जैन, लोक निर्माण, विद्युत और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सलाहकार बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान डेटा सेंटर क्लस्टर से उत्पन्न होने वाली निवेश संभावनाओं, डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने, रोजगार सृजन, तकनीकी विकास तथा क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को गति देने जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर

परियोजना के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सड़क, बिजली, सिंचाई और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने इसे क्षेत्र में आधुनिक डिजिटल अवसंरचना विकसित करने और बड़े निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।



स्थलीय निरीक्षण कर लिया जायजा

बैठक के उपरांत स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने बीडा अधिकारियों के साथ प्रस्तावित डेटा सेंटर क्लस्टर के लिए चिन्हित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परियोजना के विकास के लिए आवश्यक भूमि और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े पहलुओं का आकलन किया गया। अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित डेटा सेंटर क्लस्टर के विकास से बुंदेलखंड में डिजिटल और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। इससे निवेश के नए अवसर पैदा होंगे, रोजगार का सृजन होगा और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। यह परियोजना बुंदेलखंड को आधुनिक औद्योगिक और डिजिटल विकास के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैठक का संचालन एसीईओ प्रवीण वर्मा ने किया। उन्होंने पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से बीडा में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर क्लस्टर के लिए प्रस्तावित भूमि और परियोजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रस्तुत कीं।

रामलीला के तीसरे दिन अहिल्या उद्धार और फुलवारी लीला का मंचन

संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। गंजमुरादाबाद नगर में आयोजित श्रीरामलीला महोत्सव के तीसरे दिन अहिल्या उद्धार, नगर दर्शन और फुलवारी लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। कथा के अनुसार, भगवान श्रीराम और लक्ष्मण गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें महर्षि गौतम का सुनसान आश्रम दिखाई दिया। श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि देवराज इंद्र के छल के कारण महर्षि गौतम के शाप से अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थीं। उन्हें शाप से मुक्ति तभी मिलनी थी, जब त्रेतायुग में भगवान श्रीराम के चरणों का स्पर्श उन्हें प्राप्त होगा। जैसे ही श्रीराम के चरणों का स्पर्श शिला से हुआ, अहिल्या शापमुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गईं। उन्होंने भगवान श्रीराम की स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद महर्षि गौतम से उनका पुनर्मिलन हुआ और श्रीराम-लक्ष्मण जनकपुर की ओर आगे बढ़े। नगर दर्शन के बाद भगवान श्रीराम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका पहुंचे, जहां फूल लेने आईं माता सीता से उनका मिलन हुआ। पूरे मंचन के दौरान भक्ति संगीत और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच श्रद्धालु 'जय श्रीराम' के जयकारे लगाते रहे। इस अवसर पर श्रीरामलीला समिति के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

उन्नाव में कांग्रेस ने सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव को जयंती पर किया याद, इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि

संवाददाता



उन्नाव, उत्तर प्रदेश। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य नरेंद्र देव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीनों नेताओं के चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी। आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरदार पटेल ने देशी रियासतों का भारतीय गणतंत्र में विलय कराने में दृढ़ इच्छाशक्ति और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला उपाध्यक्ष हनुमत सिंह ने इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि उन्हें अपने अंगरक्षकों से जान का खतरा होने की सूचना मिली थी, लेकिन उन्होंने उन्हें हटाने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि ऐसा करने से एक वर्ग के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा हो सकता है। जिला उपाध्यक्ष (संगठन) चंद्र प्रकाश शुक्ला ने आचार्य नरेंद्र देव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के प्रमुख प्रणेता थे। वे महान शिक्षाविद होने के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हनुमत सिंह, चंद्र प्रकाश शुक्ला, जंग बहादुर सिंह, संजीव श्रीवास्तव, सरफराज गांधी, बाबूराम निषाद, प्रदीप वर्मा, तन्मय श्रीवास्तव सहित करीब 50 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रकाशक, मुद्रक, मालिक व संपादक सुनील कुमार हरिशंकर तिवारी द्वारा बच्ची देवी कॉपरेटीव सोसायटी, शांतिलाल कंपाउंड, गोलीबार रोड़, खार (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५५ से प्रकाशित व सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट नं. ०४, ग्राउंड फ्लोर. एन.के.इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नियर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं ०२, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-४०००६३ से मुद्रित। किसी भी खबरो के चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत संपादक जिम्मेदार। किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र मुंबई।
संपादकीय कार्यालय- एस.एस.मीडिया ग्रुप, ब्रमदीन शर्मा चॉल, जवाहर नगर, साईबाबा रोड, खार (पूर्व), मुंबई - ४०००५१, संपादकः- एस.के.तिवारी. E-mail:- ssnews2008@gmail.com, RNI. No. MAHHIN/2008/28092, Mob. 8898271111
वसई-विरार संपर्क कार्यालयः गाला नं ४, जीवदानी चाल, साई नगर, गोराई नाका, नालासोपारा (पूर्व) पालघर. सहायक संपादकः राजकिशोर तिवारी, मो. 8898771152